



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 374 राँची, शुक्रवार,

26 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

23 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप- 1-37/2017-1846 (HRMS)-- श्री वैद्यनाथ उराँव, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1974, दिनांक-23.08.2016 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-647/मनरेगा, दिनांक-30.07.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप- छत्तरपुर प्रखण्ड में डोभा निर्माण में बरती गई अनियमितता तथा JCB मशीन का उपयोग करने संबंधी श्री जवाहर मेहता से प्राप्त परिवाद के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-385 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा आपको बरती गयी अनियमितता के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

जवाहर मेहता द्वारा परिवाद दिया गया था कि पंचायत मुरमदाग, मसिहानी एवं चिरु पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण में अनियमितता एवं JCB मशीन का उपयोग होने का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में आप अपने पत्र संख्या-422 दिनांक 31.05.2016 द्वारा श्री जवाहर मेहता द्वारा छतरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा में CFT प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं नाकारात्मक विचार की वजह से मनरेगा के कार्यों में गति परिलक्षित नहीं होने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2016 को राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में डोभा निर्माण में आपसे पूछे जाने पर कि क्या यहाँ डोभा, मशीन के द्वारा बना हुआ प्रतीत नहीं होता है? इस पर आपके द्वारा अधिकांश मामले में कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड के पत्र संख्या 1691 दिनांक 26.07.2016 के द्वारा मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के द्वारा 01.06.2016 को छतरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मसिहानी, चिरु एवं मुरमदाग पंचायत में डोभा निर्माण संबंधी चल रही योजना में अनियमितता बरतने तथा JCB मशीन का उपयोग होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन में मनरेगा आयुक्त द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "इतने बड़े पैमाने पर अवैध कार्य व सरकारी राशि का अपव्यय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की संलिप्तता के बगैर संभव नहीं है। उनके द्वारा आपके विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने का अनुशंसा किया गया है"।

मनरेगा अन्तर्गत आप प्रखण्ड में मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना आपका मुख्य दायित्व है। यदि प्रखण्ड अन्तर्गत कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए आप स्वयं सीधे जिम्मेवार है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा सरकारी कार्यों में लापरवाही एवं बगैर तथ्यों एवं जानकारी के जाँच दल को स्पष्ट उत्तर नहीं देना आपके कार्यों के प्रति अभिरुचि नहीं लेना, कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है एवं मनरेगा के मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरीत है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8362, दिनांक-27.09.2016 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-9863, दिनांक-23.11.2016 एवं पत्रांक-5805, दिनांक-27.04.2017 द्वारा इन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री उराँव के पत्रांक-1023, दिनांक-10.06.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7756, दिनांक-05.07.2017 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-357/मनरेगा, दिनांक-13.06.2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री उराँव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2576(HRMS), दिनांक 23.10.2018 द्वारा श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-29, दिनांक 04.02.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-423, दिनांक 31.05.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा प्रश्नगत योजनाओं के संबंध में सिर्फ कागजातों के आधार पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

(ii) डोभा योजनाओं के विधिवत् कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से ग्राम पंचायत उत्तरदायी है।

(iii) प्रश्नगत डोभा योजनाओं में किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ था और बाद में योजनाएँ रद्द कर दी गई, इसलिए सरकारी राशि के अपव्यय को कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(iv) डोभा निर्माण संबंधी योजनाओं में जे०सी०बी० मशीन द्वारा कार्य कराये जाने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की संलिप्तता का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

(v) मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड का मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते डोभा निर्माण में जे०सी०बी० मशीन के उपयोग के लिए श्री उराँव उत्तरदायी हैं।

(vi) ग्राम पंचायत के द्वारा बरती जा रही अनियमितता पर कारगर कार्रवाई करने का दायित्व आरोपी पदाधिकारी का था, जिसमें वे विफल रहे हैं। अतः आरोपी के विरुद्ध कंडिका-4 में वर्णित आरोप "जिसमें श्री उराँव के विरुद्ध क्रियान्वित सभी योजनाओं एवं अन्य कार्यों की सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण न करने का आरोप गठित किया गया है", सही प्रतीत होता है।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री वैद्यनाथ उराँव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BAIDYANATH URAON 20080400122	श्री वैद्यनाथ उराँव, झा०प्र०से० तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
